औद्योगिक विकास को गति देने के लिए इन्वेस्ट यूपी द्वारा उद्यमी मित्रों व जिला उद्योग उप आयुक्तों (डीआईसी) की व्यापक समीक्षा बैठक 2 जून से 8 जुलाई, 2025 तक

- *उत्तर प्रदेश में निवेश परियोजनाओं की निगरानी के लिए उद्यमी मित्रों और जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमशीलता विकास केंद्र के उपायुक्तों के कार्यों की समीक्षा शुरू*

लखनऊ, 4 जून 2025: उत्तर प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन और औद्योगिक परियोजनाओं के प्रभावी जमीनी कार्यान्वयन को मजबूती देने के लिए इन्वेस्ट यूपी ने **उद्यमी मित्रों और जिला उद्योग संवर्धन एवं उद्यमिता विकास केंद्रों (डीआईसी)** के उपायुक्तों की व्यापक समीक्षा शुरू की है। यह समीक्षा मुख्य सचिव एवं अवस्थापना व औद्योगिक विकास आयुक्त **श्री मनोज कुमार सिंह** और प्रमुख सचिव, अवस्थापना व औद्योगिक विकास, **श्री आलोक कुमार** के नेतृत्व में 2 जून 2025 को प्रारंभ हुई और 8 जुलाई 2025 तक चलेगी।

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन अनुरूप प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, इस समीक्षा प्रक्रिया में 115 उद्यमी मित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये मित्र निवेशक और सरकार के बीच सेतु के रूप कार्य करते है हुए नीति संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने, भूमि अधिग्रहण में सहायता करने और औद्योगिक परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से कार्यान्वित करने में सहयोग प्रदान करते है।

इन्वेस्ट यूपी ने समीक्षा प्रक्रिया में राज्यभर के जिला उद्योग संवर्धन एवं उद्यमिता विकास केंद्रों (DICs) के उप आयुक्त और उद्यमी मित्रों को आमंत्रित किया है। प्रतिदिन तीन जिलों के प्रतिनिधि लखनऊ स्थित इन्वेस्ट यूपी कार्यालय में प्रस्तुतियां दे रहे हैं, जहां वे औद्योगिक भूमि, निष्क्रिय औद्योगिक इकाइयों की स्थिति, निवेश प्रोत्साहन व परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति, निवेश मित्र जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों से जुड़ी चुनौतियों और सुधार के लिए डेटा-आधारित कार्य योजनाएँ साझा कर रहे हैं।

यह पहली बार है कि जिला उद्योग के उपायुक्त (डीआईसी) अधिकारी इस गहन समीक्षा प्रक्रिया में सीधे भाग ले रहे हैं, जिससे विभागीय समन्वय को नई दिशा मिलेगी। इसके साथ ही, जिला स्तर पर निवेश क्षमता को उजागर करने के लिए विशेष आयोजन भी किए जाएंगे।

प्रत्येक उद्यमी मित्र और डीआईसी 180 औद्योगिक इकाइयों को सहयोग प्रदान करेंगे। उनकी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कर प्रमुख सहायता क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, जिसमें भूमि उपलब्धता और आवश्यक एनओसी शामिल हैं, ताकि वाणिज्यिक उत्पादन को सुगम बनाया जा सके, रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा सके और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को सशक्त किया जा सके।

इस समीक्षा से पूर्व, 26-30 मई, 2025 के दौरान इन्वेस्ट यूपी की टीमों—जिसमें महाप्रबंधक एवं सहायक महाप्रबंधक शामिल थे—ने चार मंडलों के 14 जिलों का दौरा किया। इस दौरान भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें औद्योगिक परियोजनाओं का निरीक्षण, नवीन औद्योगिक स्थलों की समीक्षा, निष्क्रिय औद्योगिक इकाइयों की भूमि को पुनः उपयोग में लाने हेतु सर्वेक्षण, विभागीय स्वीकृतियों एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्ति में आ रही बाधाओं की समीक्षा शामिल थी। इन निष्कर्षों को संबंधित जिलाधिकारियों के साथ साझा किया गया है, ताकि इसका प्रभावी समाधान हो सके।

जिला टीमों को उपलब्ध औद्योगिक भूमि, अन्य अधिग्रहण योग्य परिसंपत्तियों की सूची तैयार करने तथा निष्क्रिय औद्योगिक इकाइयों की भूमि को पुनः उपयोग में लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रक्रिया को गति देने और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु हर तीन महीने में फॉलो-अप समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिससे निरंतर प्रगति सुनिश्चित की जा सके।

इस समीक्षा बैठक से पूर्व, 28 अप्रैल 2025 को औद्योगिक विकास विभाग के मार्गदर्शन में इन्वेस्ट यूपी द्वारा लखनऊ में एक दिवसीय समीक्षा कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें राज्य के 75 जिलों के उद्यमी मित्रों और DIC अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्पष्ट वार्षिक लक्ष्यों को निर्धारित किया गया, जो माननीय मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश को शीर्ष निवेश गंतव्य बनाने के विजन के अनुरूप हैं।

इस पहल पर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह ने कहा: "उद्योग मित्र निवेशकों के लिए जमीनी स्तर पर अहम भूमिका निभाते हैं। यह व्यापक समीक्षा प्रक्रियागत चुनौतियों को दूर करने, जिला स्तर पर मजबूत रणनीति विकसित करने और उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख निवेश स्थल के रूप में स्थापित करने में सहायक होगी।"